एक घर जो बस न सका

यह कहानी एक ऐसे घर की है जिसे बसाने की बहुत सी कोशिशें हुयीं परन्तु वह बसते-बसते बस नहीं पाया। घर बहुत बड़ा है, सदस्य भी बहुत हैं। घर के हर प्राणी के दिल में कभी न कभी यह ख्याल आ जाता है कि काश! हम एक हो जायें।

एक होने की कल्पना में ही वे इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि घर को एकजुट करने का वास्तविक जरूरी काम ठीक से कभी नहीं हो पाता। कल्पना में वे सब विरोधियों को परास्त कर देते हैं। और कभी-कभी दो भाई, तीन भाई आपस में मेल-जोल कर, कुछ दिन इकट्ठे भी होते हैं परन्तु कुछ दिन बाद उनके बीच न जाने ऐसा क्या हो जाता है कि वर्षों तक एक-दूसरे का मुंह देखना भी पसन्द नहीं करते। फ़िर कई वर्षों बाद भी फ़िर कोई भाई ऐसा विचार रखता है कि हम एकजुट हो जायें। कुछ काम भी होता परन्तु अन्त में फ़िर वही ढाक के तीन पात। हर कोई एक-दूसरे की तरफ़ पीठ कर लेता।

घर को न बसना था न बस पाता है। यह दिलचस्प, उतार-चढाव, घात-प्रतिघात से भरी कहानी जनता दल खानदान की है।

जनता दल खानदान से निकले दलों की उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में सरकारें हैं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड), जनता दल (सेक्यूलर), बीजू जनता दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल आदि में बिखरा यह खानदान माना जाता है एकजुट होने पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ठोस चुनौती देने की क्षमता रखता है। हालिया बिहार चुनाव में तो राजद और जद (यू) की एकजुटता ने ही प्रधानमंत्री मोदी और उनके दल के छक्के छुड़ा दिये थे।

लोकसभा चुनाव के बाद जनता दल खानदान को एकजुट करने की बड़े जोर-शोर से कोशिशें हुयीं। मुलायम सिंह यादव को सर्वमान्य नेता मान लिया गया। झण्डा-डण्डा तय करने का उन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया। बस अखिल भारतीय पार्टी की घोषणा के कुछ औपचारिकताएं ही शेष थीं कि मुलायम सिंह के अपने खानदान में इस एकता को लेकर खुसुर-पुसुर शुरू हो गयी। रही-सही कसर बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे ने पूरी कर दी। मुलायम सिंह कम सीटें दिये जाने पर नाराज हो गये और ऐसी स्थिति में नहीं रहे कि लालू-नीतिश को बधाई दे सकें।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक तो पहले दिन से ही इस एकता की कवायद से दूर थे। वे अपने खानदान से मिलने वाले निमंत्रण पत्र को रद्दी की टोकरी के हवाले करते रहे। उन्होंने एकता के हसीन सपने को अपने अनुभव से तौला, यथार्थ से जोड़ा और अंत में अपने खानदान में सबसे सयाने साबित हुए।

लालू प्रसाद यादव ने एकता की खातिर अपनी एक बेटी की शादी मुलायम सिंह यादव के परिवार में करा दी। दोनों समधी बन गये। विचारों की एकता के लिये रिश्तेदारी के पवित्र बंधन का अभिनव प्रयोग किया गया परन्तु लालू का यह तीर निशाने पर ठीक नहीं बैठा। गलती शायद दोनों से हो गयी कि शादी के अवसर पर खास मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को बुला लिया। लालू और मुलायम ने मोदी का खूब जोर-शोर से स्वागत किया। इस बीच में मोदी ने मुलायम को न जाने धमकाया या पटाया पर कुछ ऐसा हुआ कि मुलायम की भाषा बदल गयी। एकता का नशा उतर गया और वे संसद में कांग्रेस की योजनाओं पर पलीता लगाने लगे।

अब स्थिति यह है कि जनता दल खानदान को एकजुट करने की कोई बात नहीं कर रहा है। सब चुप हैं। अपने-अपने कुनबे को लेकर बैठे हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद यह कवायद शुरू हुयी थी अब लगता है फ़िर जब चुनाव आयेंगे तब फ़िर से यह कवायद शुरू हो।

अब थोड़ा गम्भीरता से सोंचे कि यह खानदान क्यों एकजुट नहीं हो सकता है। क्यों इसके भाग्य में यह सब लिखा हुआ है।

जनता दल परिवार की जितनी भी पार्टियां हैं इनका आधार पिछड़ी जातियों में है। पिछड़ी जातियां, किसान जातियां हैं। और इन जातियों के देहाती पूंजीपति ही इन पार्टियों के मुख्य रीढ हैं। व्यापारिक पूंजी, नौकरशाही, स्थानीय औद्योगिक पूंजी में भी इनका आधार है परन्तु मूलत:देहाती पूंजीपति वर्ग ही इनका सिरमौर है और वही इन पार्टियों को अपनी जाति के मझोले-छोटे किसानों से लेकर खेतिहर मजदूरों को अपने पीछे लामबंद कर जनाधार मुहैय्या कराता है। शहरी पूंजीपति व मध्यम वर्ग पार्टियों का छिट-पुट ढंग से ही सहयोगी है। मूलत: वह आलोचक और वह कांग्रेस, भाजपा जैसी पार्टियों को तरजीह देता है। इस तरह जनता दल परिवार की पार्टियों को जिन पार्टियों से मुख्यत: होड़ करनी होती है वह कांग्रेस, भाजपा या अपनी जैसी पार्टियों ये होड़ करनी होती है। कांग्रेस, भाजपा जैसी पार्टियों का भले ही आबादी के विभिन्न हिस्सों हिस्सों में आधार हो परन्तु ये भारत की एकाधिकारी पूंजी से संचालित हैं। एकाधिकारी पूंजी इन पार्टियों के मार्फ़त देश की सरकार के गठन से लेकर नीतियों के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है।

क्षेत्रीय, देहाती पूंजीपति वर्ग की पार्टियों के देश में विविध किस्म हैं परन्तु जनता दल परिवार इस पूंजी की खास जाति आधारित पार्टियां हैं। इन पार्टियों का विकास और विस्तार एक सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता। और देश के पैमाने पर एक होने में इनकी आपसी होड़, हितों की टकराहट के साथ-साथ देश की सत्ता पर मूलत: काबिज एकाधिकारी पूंजी के साथ रिश्ते आड़े आ जाते हैं। यदि वे ऐसा कुछ करते हैं जो देश की केन्द्रीय सत्ता को चुनौती दे तो केन्द्रीय सत्ता में बैठी पूंजी उन्हें सबक सिखाने के लिये साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति का ऐसा इस्तेमाल कर सकती है कि मुलायम सिंह नीतिश-लालू के गले मिलते-मिलते, नरेद्र मोदी के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। नवीन पटनायक ऐसी किसी गोलबंदी में नहीं जाते हैं जो उनके सामने ऐसी समस्यायें खड़ी कर दे जिनका समाधान नई दिल्ली से हो सकता है।

गैर एकाधिकारी पूंजियो की नियति है कि वह विशाल एकाधिकारी पूंजी के सामने टिक नहीं सकती हैं। वह ऐसा संघर्ष भी नहीं कर सकती जो एकाधिकारी पूंजी को उसके स्थान से हटा सके। वह रो सकती है, शिकायतें कर सकती है, अनुदान-बजट सहायता की मांग कर सकती है, पड़ोसी राज्य से तुलना कर उलाहना दे सकती है परन्तु उसकी बनावट ही ऐसी नहीं है कि वह एकजुट हो सके, चुनौती दे सके। बिखरना, टूटना ही उसके भाग्य में बदा है। -नागरिक

जनता डॉक्टरों को आज भी भगवान के रूप में देखती है

बिलासपुर : देश की जनता भले ही अपना इलाज करने वाले डॉक्टरों को आज भी भगवान के रूप में देखती हो लेकिन सच्चाई यह है कि इस पेशे से जुड़े हुए लोग अब व्यवसायिक बन चुके हैं । उन्हें मरीज से नहीं अपने पैसे से लगाव है । मरीज मरे या जिन्दा रहे उनको उनके पैसे जरूर मिलने चाहिए। कुछ ऐसा ही वाक्या बिलासपुर में सामने आया है। तीरंदाजी के लिए देश का नाम रोशन करने वाली राष्ट्रीय खिलाड़ी शांति धांधी की मौत के बाद उसका शव अपोलो अस्पताल के मैनेजमेंट ने इसलिए देने से मना कर दिया क्योंकि उसका 2 लाख रुपये का बिल बकाया था।।

लाख मिन्नतों के बाद भी जब प्रबंधन नहीं माना तो मृतका की बहन डॉक्टरों के सामने जाकर रोने लगी । उसने डॉक्टरों से कहा- पैसे के बदले में जब तक चाहो मुझे रख लो, मुझे गिरवी रख लो, मुझसे जो काम चाहो करवा लो लेकिन मेरी बहन की लाश दे दो। उसे यहां पर बंधक मत बनाओ, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा तो सब कुछ इलाज में लुट चुका है। इतनी मिन्नत के बाद प्रबंधन ने रकम जमा करने की बात लिखित में लेकर शव परिजनों को सौंपा।

कैसे हुई मौत खिलाडी की

बताया जाता है कि कोरबा के मुड़ापार के रहने वाली 18 साल की शांति धांधी का लीवर फेल हो गया था। एसईसीएल कोरबा अस्पताल से उसे 14 मार्च को अपोलो रेफर किया गया। 14 मार्च से उसका इलाज अपोलो में चल रहा था, बीते शनिवार की रात करीब एक बजे उसकी मौत हो गई। युवती के इलाज के दौरान उसकी बहन सावित्री धांधी और पड़ोस में रहने वाला उसका भाई कैलाश साहू साथ थे।

इलाज के नाम पर धन बटोरने का आरोप

जब उन्हें मौत का पता चला तो उन्होंने रात में ही परिजनों को सूचना दे दी। अपोलो प्रबंधन ने परिजनों से बिल का हिसाब करने के लिए कहा- सावित्री और कैलाश बिल पूछने के लिए पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि 2 लाख 19 हजार रुपए और जमा करना है। इस पर परिजनों ने कहा वे उतना पैसा नहीं दे सकते। बिल क्लीयरेंस नहीं होने पर प्रबंधन ने शव को मोरचरी में भिजवा दिया। दोनों भाई-बहन ने रविवार सुबह तक अलग-अलग जगहों से पैसे का इंतजाम करने की कोशिश की लेकिन हो न सका। इसके बाद बहन के गुहार लगाने पर शव सौंपा गया। वहीं भाई कैलाश का आरोप है कि अपोलो में इलाज नहीं होने के बाद भी जबरिया मरीज को वहां पर रखकर बिल बढ़ाया जा रहा था।

इस तरह लाश को जबरन रोकना कानूनन जुर्म भी है जो न पुलिस को दिखाई दे रहा है और न न्यायालय को और न मोदी-राजनाथ-रमण सिंह को।

नायक नहीं खलनायक हूँ मैं............

मोदी की नायक बनने की तमन्ना नेहरू को उनसे गाली दिलवा रही है । मोदी खुद तो नायक बनने की हसरत पूरी नहीं कर सके, तो देश के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू को खलनायक सिद्ध करने की मुहिम पर निकल पड़े हैं ।

आज़ादी के तत्काल बाद के कुछ सालों के बारे में आजकल कई अनर्गल सवाल उठाए जा रहे हैं और ग़लत धारणाएँ जनता के मन में बैठाई जा रही हैं। उन सब का उद्देश्य है - किसी न किसी प्रकार पंडित नेहरू को खलनायक दिखाना। जैसे सरदार पटेल को पहला प्रधान मंत्री क्यों नहीं बनाया गया -वह नेहरू जी से बेहतर साबित होते। या 1951 में अंबेडकर ने केन्द्रीय मंत्रीमंडल से इस्तीफ़ा क्यों दिया था।

महात्मा गाँधी के पोते राजमोहन गाँधी उस समय के इतिहासकार है। उन्हेंने इकनोमिक टाइम्स से एक इंटरव्यू मेँ इन सहित कई सवालों का जवाब दिया -

एक - 1947 में सरदार पटेल नेहरू जी से पन्द्रह साल बड़े थे, बीमार थे. महात्मा गाँधी ने नेहरू को प्रधान मंत्री बनाना सही समझा।

दो - अंबेडकर ने इस्तीफ़ा नेहरू से मतभेद के कारण नहीं, हिंदू कोड बिल के विरुद्ध हिदू लाबी के बढ़ते दबाव से तंग आ कर दिया। जो छलिया इतिहास आज के आम आदमी को बताया जा रहा है - उसका निराकरण ज़रूरी है।

तुर्की-ब-तुर्की / खुद चोरी कराते हैं फिर चोर पकड़ने का नाटक

''बैंकों का पैसा जनता का पैसा है। इसे लेकर भागने वालों को हमारी सरकार कहीं से भी पकड़ कर लायेगी।'' (असम की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दावा)

''हमारा कहना है-

. लगे हाथ मोदी जी यह भी स्पष्ट कर दीजिये कि अभी तक आपकी सरकार ने बैंक कर्ज़ के कितने डिफ़ाल्टर जेल में डाले हैं? अगर वाकई आपकी नीयत जनता का पैसा लेकर डकारने वालों को पकड़ने की होती तो अब तक जेल जाने वाले उद्योगपतियों की लाइन लग गयी होती। जबकि आज तक आपकी सरकार इस मामले में खाता तक भी नहीं खोल पाई है।

. शराब कार्पोरेट विजय माल्या आपकी एन नाक के नीचे से बैंकों यानी जनता के 9000 करोड़ लेकर बड़े आराम से खिसक लिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि माल्या के पलायन की पूरी जानकारी आपको व आपके वित्त मन्त्री अरूण जेटली को दी गयी थी। पर हुआ यह कि पंछी उड़ जाने के बाद जाल बिछाने का नाटक किया गया। सम्बन्धित बैंकों से माल्या का पासपोर्ट जब्त करने और उसे गिरफ़्तार करने की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में तब दिलवाई गयी जब माल्या देश से फ़रार हो चुका था। ज़्यादातर रकम तो वह पहले ही हवाला आदि के माध्यम से भारत के बाहर भेज चुका था। 2 मार्च को प्रइवैट जेट से फ़रार होते हुए बाकी की रकम वह 9 बड़े-बड़े सूटकेसों में भरकर साथ ले गया। मोदी जी क्या आपको यह जग-जाहिर बात नहीं पता? या तो आप अपना पुराना धूर्तता का खेल खेलने में लगे हैं और या आप बेहद नाकारा सरकार चला रहे हैं।

. अपने अपराधों को अपनी सफ़लतायें बताने में आपका कोई सानी नहीं। कहां तो माल्या के भाग जाने पर आपको शर्मिंदा होना चाहिये था। और कहां आप चुनावी सभाओं में सीना तानकर अपने इस राष्ट्र विरोधी कुकृत्य पर अपनी ही पीठ ठोंकने में लगे हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब आपने अपने परम मित्र गौतम अडानी को आस्ट्रेलिया में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरपर्सन के हाथों 6000 करोड़ का कर्ज़ दिलवाया था। आज नहीं तो कल यह पैसा भी डूबना है। जाहिर है तब भी मोदी जी आप कोई न कोई तर्क ढूंढ ही लेंगे जो जनता की नज़रों में आपको और बड़ा देशभक्त सिद्ध करे।

. असली सवाल तो आप खा ही गये। क्या बैंक के बड़े-बड़े अधिकारी इतने दु:साहसी हैं कि अपनी पूंजी लुटाने का काम धड़ल्ले से करते हुए सामने वाले की पड़ताल भी नहीं करते? कौन नहीं जानता कि जालसाज पूंजीपतियों को सैंकड़ों-हज़ारों करोड़ के कर्ज़े सत्ताधारियों के सक्रिय सहयोग से ही संभव होते हैं। जैसा कि माल्या के मामले में कांग्रेसी शासन में हुआ था और अब आपके शासन में अडानी के मामले में हो रहा है। ऐसे में सम्बन्धित बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न होना क्या दर्शाता है? आपकी, आपके वित्त मन्त्री की और आपकी सरकार की मिलीभगत छिपाये नहीं छिप सकती।